के, कन्नन, जे. के समक्ष।

रमेश कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड

और एक अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. **2003** का **14980**

मार्च **23,2012**

*भारत का संविधान, **1950** - अनुच्छेद **226** - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड - बीबीएमबी में सीएफओ और पीएसईबी में एसडीओ - क्या वेतन के संबंध में दो अलग-अलग संगठनों में दो अलग-अलग पदों पर समानता दी जा सकती है -यह केवल तराजू में एक पेटेंट अतार्किकता है जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी - जो नीति बीबीएमबी द्वारा ली गई थी जो पीएसईबी स्केल को लागू करेगी उसे बीबीएमबी में सीएफओ के पद को एसडीओ के पद के रूप में मानने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए -पीएसईबी में एसडीओ के पद के लिए कुछ निश्चित पैमानों के साथ सीएफओ के लिए आवेदन किया जाना चाहिए - जिस तारीख से व्यक्ति ने पद संभाला है, उस तारीख से **9/16** साल की सेवा के बाद एसडीओ के लिए प्रमोशनल या चयन ग्रेड, उसे सीएफओ के पद के लिए भी आवेदन करना चाहिए - **9/16** साल की सेवा के संदर्भ में उच्च वेतनमान उस तारीख से होना चाहिए जब व्यक्ति ने उस पद पर कब्जा किया था, न कि उस तारीख से जब आदेश पारित हुआ था।*

*माना गया कि इस सिद्धांत को समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि न्यायिक हस्तक्षेप स्वयं न्यूनतम होगा जब उसके पास विभिन्न पदों में वास्तविक नौकरी सामग्री को मापने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होगी और क्या दो अलग-अलग संगठनों में दो अलग-अलग पदों पर वेतन के संबंध में समानता दी जा सकती है। यह केवल तराजू में एक पेटेंट अतार्किकता है जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अब कोर्ट का यह देखने का प्रयास नहीं है कि सीएफओ और एसडीओ के पदों के लिए काम का घटक कहां समान था। जाहिर तौर पर वे नहीं थे. हालाँकि, मुद्दा यह है कि बीबीएमबी, जो नंगल परियोजना का उत्तराधिकारी था, के पास इस बात का एक पुराना उदाहरण था कि कैसे सीएफओ पद को एसडीओ के रूप में पुनः नामित किया गया था और इसके बाद वर्ष **1981** में जब सीएफओ को केवल दुर्घटना के*

मामले के रूप में नहीं बल्कि एसडीओ के पद के बराबर मानने की एक सोची-समझी नीति के तहत टीआईसी स्केल दिया जा रहा था और स्केल लागू करने के लिए ऐसे पद का विशेष संदर्भ दिया गया था, तब मैं यह मानूंगा कि बीबीएमबी द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, जो पीएसईबी स्केल को लागू करेगी, उसे बीबीएमबी में सीएफओ के पद को एसडीओ के पद के रूप में मानने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और पीएसईबी के साथ उसी पद के लिए पैमाने की समानता की तलाश करनी चाहिए। नतीजतन, यदि पीएसईबी में एसडीओ का पद था जो कुछ निश्चित पैमाने प्रदान करता था, तो उसे सीएफओ के लिए भी लागू किया जाना चाहिए था। यह चयनात्मक तरीके से पीछे नहीं हट सकता था कि उसने पहले सीएफओ के पद के साथ कैसा व्यवहार किया था और केवल पीएसईबी वेतनमान का भुगतान न करने का विकल्प चुनने के लिए सीएफओ के पद की पहचान बरकरार रखी थी। जब पीएसईबी वेतनमान लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया गया, तो यह निश्चित रूप से एक और बड़े संगठन के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने का एक तरीका था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विभिन्न पदों पर काफी व्यापक नौकरी संरचना और वेतनमान थे। जितना बड़ा या मैं बीबीएमबी से बड़ा नहीं। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सेवा की अधिक लाभकारी शर्तों का विस्तार करना था, जिसे पीएसईबी स्केल के उदाहरण के रूप में देखा जाए।

(पैरा 4)

*आगे कहा गया है, कि मेरे विचार के तार्किक विस्तार के रूप में कि पीएसईबी स्केल को एसडीओ के लिए लागू किया जाना चाहिए, यदि पीएसईबी में, उस तारीख से **9/16** साल की सेवा के बाद एसडीओ के लिए पदोन्नति या चयन ग्रेड था जब व्यक्ति ने पोस्ट किया था , इसे सीएफओ के पद पर भी लागू किया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश इसे केवल उस तारीख से प्रभावी बनाता है जब आदेश पारित किया गया था। मुझे यह अवश्य देखना चाहिए कि सीएफओ का पद अपने आप में एक अकेला पद था और इसमें पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं था। एक निश्चित संख्या में वर्षों के बाद पदोन्नति/निर्धारित पदोन्नति वेतनमान का प्रावधान ठहराव को रोकने और कैरियर की प्रगति में संभावित सुधार के बिना लंबे समय तक पद पर रहने वाले कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करने के लिए था। यह बिल्कुल तर्कसंगत था कि ऐसे उच्च वेतनमान उस विशेष पद पर सेवा के वर्षों की संख्या के संदर्भ में होने चाहिए और वेतनमान प्रदान करने वाले ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख पर निर्भर नहीं किया जा*

*सकता है। **9/16** वर्ष की सेवा के संदर्भ में उच्च वेतनमान की शुरुआत उस तारीख से होनी चाहिए जब व्यक्ति ने उस पद पर कब्जा किया था, न कि उस तारीख के संदर्भ में जब आदेश **24.07.2003** को पारित हुआ था।*

(पैरा 5)

सूरम सिंह राणा, याचिकाकर्ता के वकील।

प्रतिवादियों की ओर से अंकित गोयल, अधिवक्ता।

के. कन्नन, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता, जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संक्षेप में, बीबीएमबी) में मुख्य पीआरसी अधिकारी (संक्षेप में, सीएफओ) है, 24.07.2003 को जारी आदेश को रद्द करने की मांग करता है (अनुलग्नकपी-14), पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (संक्षेप में, पीएसईबी) प्रतिष्ठान में उप मंडल अधिकारी (संक्षेप में, एसडीओ) के पद पर लागू वेतनमान के बराबर 9/16 साल की सेवा के बाद पदोन्नति/तैयार पदोन्नति वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। समानता की मांग इस आधार पर की गई थी कि बीबीएमबी ने पीएसईबी में उपलब्ध पदों के लिए 26.06.1992 को पीएसईबी वेतनमान अपनाने का निर्णय लिया था।याचिकाकर्ता ने पीएसईबी के साथ एसडीओ के पद के लिए समानता का दावा किया, लेकिन चूंकि पीएसईबी के साथ सीएफओ का कोई पद नहीं था, इसलिए बीबीएमबी ने सीएफओ के पद के लिए अपने स्वयं के पैमाने निर्धारित करने का विकल्प चुना और याचिकाकर्ता द्वारा सीएफओ के रूप में कार्य करना शुरू करने की तारीख से पदोन्नति/तैयार पदोन्नति वेतनमान के बजाय 24.07.2003 को आदेश जारी होने की तारीख से 9/16 साल की सेवा के बाद पदोन्नति/तैयार पदोन्नति वेतनमान के लिए भी प्रावधान किया गया।

(2) समानता का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता का आधार यह था कि उसका हमेशा से अनुभव रहा है कि सीएफओ को एसडीओ के समान वेतनमान पर रखा गया था। यह महज संयोग की बात नहीं थी, बल्कि यह एक सचेत निर्णय था जो बोर्ड के गठन से भी पहले 20.09.1955 की अवधि से संबंधित था। याचिकाकर्ता नंगल टाउनशिप के निर्माण और संयंत्र डिजाइन निदेशालय की कार्यवाही के एक उदाहरण पर भरोसा करेगा कि अग्निशमन अधिकारी का कार्यालय उप प्रभागीय अधिकारी के कार्यालय में बदल दिया गया था और एक विशेष कर्मचारी ए.एन. अहलूवालिया, जो एक अग्निशमन अधिकारी थे, को उपखण्ड अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया गया। इसके बाद फिर से बोर्ड के गठन के बाद जब

सीएफओ श्री टीएन कौल को स्थायी रूप से बीबीएमबी में समाहित कर लिया गया, तो बोर्ड ने सीएफओ के कार्यालय में एसडीओ के पद के संशोधित वेतनमान की अनुमति दी। इसलिए, याचिकाकर्ता दावा करेगा कि जब बोर्ड द्वारा पीएसईबी के वेतनमान लागू करने का निर्णय लिया गया था, वह एसडीओ के डाक पीएसईबी से जुड़े वेतनमान देने के हकदार थे और बीबीएमबी को केवल इस कारण से एक अलग मानदंड लागू नहीं करना चाहिए था कि पीएसईबी में सीएफओ का कोई पद नहीं था।

(3) 'एफसीएच याचिकाकर्ता का दावा है कि सीएफओ के लिए शैक्षणिक योग्यता भी एसडीओ की योग्यता से कम नहीं थी। उत्तरदाताओं द्वारा विशेष रूप से यह कहकर खंडन किया गया है कि सीएफओ के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता फायर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या उस क्षेत्र में 2 से 3 साल के अनुभव के साथ समकक्ष है जबकि एसडीओ के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री थी। यहाँ तक कि कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की प्रकृति भी एक समान नहीं थी। उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील का तर्क होगा कि केवल एक तथ्य यह है कि किसी समय सीएफओ और एसडीओ के लिए वेतनमान में समानता थी, ऐसी स्थिति में अतार्किक रूप से नहीं लिया जा सकता है जहां सीएफओ के रूप में वास्तविक पद पीएसईबी में मौजूद नहीं था और पीएसईबी स्केल लागू करने का नीतिगत निर्णय केवल उन वास्तविक पदों तक ही सीमित होना चाहिए जो बीबीएमबी में पदों के अनुरूप पीएसईबी में मौजूद थे। विद्वान वकील *पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल न्यूनतम वेतन निरीक्षक संघ और अन्य*[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करेंगे, जिसमें कहा गया था, 'समान काम के लिए समान वेतन' की याचिका और वेतन में समानता के दावे की जांच करते समय न्यायालय उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए कैसे हस्तक्षेप करेगा, इस संदर्भ में: -

"22. रिट याचिका में दावा इस आधार पर नहीं था कि विषय पद और संदर्भ श्रेणी के पदों में समान या समान कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, बल्कि इस तर्क पर आधारित था कि विषय के रूप में प्रधान मंत्री/धारक और संदर्भ श्रेणी के पदों के धारक जो पूर्व समय में समान वेतन का आनंद ले रहे थे, उन्हें वेतन संशोधन के बाद भी समान वेतन दिया जाना जारी रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दावा की गई समानता समान काम के लिए समान वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले समान वेतन के आधार पर थी।

---

[1] **(आई) (2010)5** एससीसी **225**

23. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि समानता का दावा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि पहले विषय पद और संदर्भ श्रेणी के पदों का वेतनमान समान था। वास्तव में, वेतन आयोग का एक कार्य उन पदों की पहचान करना है जो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में पहले की तुलना में अधिक वेतनमान के पात्र हैं, और उन श्रेणियों के पदों के लिए ऐसे उच्च वेतनमान का विस्तार करना है।

25. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक पद जिसे कम वेतनमान वाला माना जाता है उसे उच्च वेतनमान दिया जा सकता है और दूसरे पद जिसे उचित वेतनमान वाला माना जाता है उसे केवल संबंधित संशोधित वेतनमान दिया जा सकता है लेकिन कोई उच्च वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, उच्च वेतनमान के लाभ का दावा केवल यह स्थापित करके किया जा सकता है कि विषय पद के धारक और संदर्भ श्रेणी के पदों के धारक, एक-दूसरे के समान या समान कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करते हैं और असमानता की निरंतरता तर्कहीन और अन्यायपूर्ण है। इसलिए, वकील का तर्क होगा कि विषय पद और संदर्भ श्रेणी के पदों के धारक को स्केल का लाभ केवल स्केल की समानता के लिए दिया जा सकता है यदि कर्तव्य और कार्य एक दूसरे के समान या समान थे और यदि असमानता की निरंतरता तर्कहीन और अन्यायपूर्ण है।

(4) इस सिद्धांत को समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि न्यायिक हस्तक्षेप स्वयं न्यूनतम होगा जब उसके पास विभिन्न पदों में वास्तविक नौकरी सामग्री को मापने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होगी और क्या दो अलग-अलग संगठनों में दो अलग-अलग पदों पर वेतन के संबंध में समानता दी जा सकती है। यह केवल तराजू में एक पेटेंट अतार्किकता है जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अब न्यायालय का यह देखने का प्रयास नहीं है कि सीएफओ और एसडीओ के पदों के लिए काम का घटक कहाँ समान था। जाहिर तौर पर वे नहीं थे हालाँकि, मुद्दा यह है कि बीबीएमबी, जो नंगल परियोजना का उत्तराधिकारी था, के पास इस बात का एक पुराना उदाहरण था कि कैसे सीएफओ पद को एसडीओ के रूप में पुनः नामित किया गया था और बाद में वर्ष 1981 में जब सीएफओ को केवल दुर्घटना के मामले के रूप में नहीं बल्कि एसडीओ के पद के बराबर मानने की एक सोची-समझी नीति के तहत वेतनमान दिया जा रहा था और वेतनमान लागू करने के लिए ऐसे पद का विशेष संदर्भ दिया गया था, तब मैं यह मानूंगा कि बीबीएमबी द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, जिसमें पीएसईबी स्केल लागू होगा, उसे बीबीएमबी में सीएफओ के पद को एसडीओ के पद के रूप में

मानने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और पीएसईबी के साथ उसी पद के लिए स्केल की समानता की तलाश करनी चाहिए। नतीजतन, यदि पीएसईबी में एसडीओ का कोई पद था जो कुछ निश्चित पैमाने प्रदान करता था, तो उसे सीएफओ के लिए भी लागू किया जाना चाहिए था। यह चयनात्मक तरीके से पीछे नहीं हट सकता था कि उसने पहले सीएफओ के पद के साथ कैसा व्यवहार किया था और केवल पीएसईबी वेतनमान का भुगतान न करने का विकल्प चुनने के लिए सीएफओ के पद की पहचान बरकरार रखी थी। जब पीएसईबी स्केल लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया गया, तो यह निश्चित रूप से एक और बड़े संगठन के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने का एक तरीका था, जिसके पास काफी व्यापक नौकरी संरचना थी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों पर वेतनमान, बीबीएमबी से बड़ा या नहीं तो बड़ा। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी दसियों सेवा का विस्तार करना था, जिसे वह पीएसईबी स्केल के उदाहरण के रूप में देखता है।

(5) मैंने कैसे माना है कि पीएसईबी स्केल को एसडीओ के लिए लागू किया जाना चाहिए, इसके तार्किक विस्तार के रूप में, यदि पीएसईबी में, उस व्यक्ति के पद संभालने की तारीख से 9/16 साल की सेवा के बाद एसडीओ के लिए पदोन्नति या चयन ग्रेड था , इसे सीएफओ के पद पर भी लागू किया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश इसे केवल उस तारीख से प्रभावी बनाता है जब आदेश पारित किया गया था। मुझे यह अवश्य देखना चाहिए कि सीएफओ का पद अपने आप में एक अकेला पद था और इसमें पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं था। एक निश्चित संख्या में वर्षों के बाद पदोन्नति/तैयार पदोन्नति वेतनमान के प्रावधानों का उद्देश्य स्थिरता को रोकना और कैरियर की प्रगति में संभावित सुधार के बिना लंबे समय तक पद पर रहने वाले कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करना था। यह बिल्कुल तर्कसंगत था कि ऐसे उच्च वेतनमान उस विशेष पद पर सेवा के वर्षों की संख्या के संदर्भ में होने चाहिए और वेतनमान प्रदान करने वाले ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। 9/16 वर्ष की सेवा के संदर्भ में उच्च वेतनमान की शुरुआत उस तारीख से होनी चाहिए जब व्यक्ति ने उस पद पर कब्जा किया था, न कि उस तारीख के संदर्भ में जब आदेश 24.07.2003 को पारित हुआ था।

(6) आक्षेपित अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर परिणामी मौद्रिक लाभ का भुगतान करने के लिए उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका को अनुमति दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा